ग्रीन रिवोल्ट

हरित-नीरा रहे वसुंधरा

पेजः 4

पाम ऑयल पैदा करने की कीमत चुका रहे हैं इंडोनेशिया के आदिवासी

रविवारीय, 24- 30 जनवरी 2021 वर्ष- दो, अंक-25, रांची, कुल पृष्ठ 4 हिन्दी साप्ताहिक R.N.I. No. JHAHIN/2019/78094 www.greenrevolt.news मूल्यः 5 रूपये

आप सभी प्रिय पाठकों को गणतंत्र दिवस के सुअवसर पर ग्रीन रिवोल्ट परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। ग्रीन रिवोल्ट सदैव आप सुधि पाठकों की कसौटियों पर खड़ा उतरने को प्रयासरत है।

ग्रीन रिवोल्ट के पाठकों से आग्रह है कि आप पर्यावरण, कृषि, जल संरक्षण, पशुपालन, बागवानी , पेट्स, वृक्षारोपण से संबंधित खबरें, समस्यायें, लेख,सुझाव, प्रतिक्रियायें या तस्वीरें हमें अवश्य भेजें। हमारा इमेल एवं हवाट्सएप नंबर है।

greenrevolt2019@gmail.com

9798166006

देश में अब तक हाशिये पर रहा किसान नये कृषि कानूनों पर केंद्र से दो दो हाथ करने के लिये तैयार, अब

गणतंत्र दिवस पर किसानों का मार्च

वरीय संवाददाता

देश में पहला गणतंत्र दिवस ऐसा है जब राष्ट्रीय राजधानी में अलग-अलग हिस्सों से हजारों किसानों का जत्था सरकार की रजामंदी से नहीं बल्कि पुलिस की कागजी अनुमति से किसान रिपब्लिक परेड के लिए दाखिल हो रहा है। किसानों की इस ट्रैक्टर परेड के लिए दिल्ली के तीन प्रमुख रास्तों से इंट्री की इजाजत दी गई है, इनमें सिंघु , टिकड़ी व गाजीपुर बॉर्डर शामिल हैं। हालांकि, किसानों की ट्रैक्टर परेड तभी शुरू होगी जब राजपथ की आधिकारिक परेड खत्म हो जाएगी। वहीं, किसान नेताओं ने 25 जनवरी, 2021 को जारी बयान में कहा कि 01 फरवरी, 2021 को, जिस दिन बजट जारी किया जाएगा उस दिन किसान पैदल ही संसद का घेराव भी करेंगे।

दिल्ली पुलिस की तरफ से जिन रूट पर किसानों को ट्रैक्टर रैली की इजाजत दी गई है उनमें सिंघु बॉर्ड का रूट कुल 63 किलोमीटर का होगा। टिकड़ी का रूट 62.5 किलोमीटर का होगा और गाजीपुर का रूट 68 किलोमीटर का होगा।

दिल्ली की सीमाओं पर तीन नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान यूनियनों को 62 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। 11 बार सरकार के साथ बैठक हुई है लेकिन बैठकें निस्सार रही हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने अपने बयान में कहा है कि तीनों कृषि बिलों को खत्म करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) लागू करने की मांग जारी है और देशभर के किसानों से इसका समर्थन मिल रहा है। आंदोलन में अब तक 151 से अधिक किसानों की जान जा चुकी है। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक उ-ड़ीसा से किसान दिल्ली चलो यात्रा के तहत किसान गाजीपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। वहीं, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश से किसान परेड के लिए शामिल हो चुके हैं। इसके अलावा गुजरात खीदत मंच से जुड़े हुए 200 महिला और 300 पुरुष किसान भी यूपी के शाहजहांपुर से होते हुए दिल्ली के रास्ते में हैं।

कई राज्यों में भी किसान राजधानी और जिला स्तर पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड के गढ़वा में पैदल मार्च और रांची में किसान स्थानीय लोग राजभवन की तरफ मार्च निकालेंगे। जबकि मध्य प्रदेश में भोपाल, भिंड, ग्वालियर में भी मार्च निकाली जाएगी। इसके अलावा बिहार में दरभंगा व भोजपुर में कई स्थानों पर प्रदर्शन होंगे।

क्या करना है और क्या नहीं करना है, यह भी हिदायत किसानों ने तय किया

परेड में ट्रैक्टर और दूसरी गाड़ी चलेंगी, लेकिन ट्रॉली नहीं जाएगी। जिन ट्रालियों में विशेष झांकी बनी होगी उन्हें छूट दी जा सकती है। पीछे से ट्रॉली की सुरक्षा का इंतजाम करके जाएं। अपने साथ 24 घंटे का राशन पानी पैक क-रके चलें। जाम में फंसने पर ठंड से बचाव का इंतजाम भी रखें। संयुक्त किसान मोर्चा की अपील है कि हर ट्रैक्टर या गाड़ी पर किसान संगठन के झंडे के साथ-साथ राष्ट्रीय झंडा भी लगाया जाए। किसी भी पार्टी का झंडा नहीं लगेगा। अपने साथ किसी भी तरह का हथियार ना रखें, लाठी या जेली भी ना रखें। किसी भी भड़काऊ या नेगेटिव नारे वाले बैनर ना लगाएं।

भारतीय संविधान और हमारा पर्यावरण

सत्यनारायण गुप्ता

विगत 13 जनवरी को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने एक मामले की सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की कि साफ पर्यावरण और प्रदूषण रहित जल अर्थात शुद्ध जल व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और इसे सुनिश्चित करना कल्याणकारी राज्य का संवैधानिक दायित्व है ।साथ ही प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्रकृति जैसे वन, नदी झील और वन्य प्राणियों का संरक्षण और रक्षा करें। सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी दिल्ली जल बोर्ड की हरियाणा से आ रहे पानी में प्रदूषण की शिकायत से संबंधी याचिका पर सुनवाई के क्रम में की ।

हम भारतवासियों की एक बड़ी समस्या यह रही है कि हमारे नैसर्गिक अधिकारों और कर्तव्यों को भी देश की सर्वोच्च न्यायालय को याद दिलाना पड़ता है। जब हम भारतीय संविधान को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि हमारे संविधान निर्माता कितने आगे की सोचते थे। वास्तव में प्रकृति और पर्यावरण संबंधी चिंताएं दिनों दिन बढ़ती गई है। वर्ष 2020 इतिहास में अब तक का सबसे गर्म वर्ष रहा है तथा पिछला दशक (2011 से 2020) सबसे गर्म दशक। लेकिन लगता है कि हमारे संविधान निर्माताओं को इस समस्या का पूर्वानुमान था तभी तो संविधान में ऐसे उपबंध शामिल किए जिससे सरकार और आम नागरिक पर्यावरण के लिए प्रेरित हों।

भारतीय संविधान का भाग 3 प्रत्येक नागरिक को कुछ मौलिकअधिकार देता है। अनुच्छेद 19(1)(a)और अनुच्छेद21 प्रत्येक नागरिक को अच्छे वातावरण और शांतिपूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है ।अनुच्छेद 21 जीवन जीने का अधिकार देता है ,इसमें स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, बीमारियों और संक्रमण के ख़तरे से मुक्ति का अधिकार अंतर्निहित। एम.सी.मेहता केस (1987)तथा देहरादून खदान केश(1988))में सर्वोच्च न्यायालय ने क्रमशः प्रदूषण रहित वातावरण में जीवन जीने के अधिकार को मान्यता दी थी तथा पर्यावरण संतुलन के मद्देनजर गैरकानूनी खनन रोकने के निर्देश दिए थे।

अनुच्छेद 19(1) (a) प्रत्येक नागरिक को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करता है। लेकिन इस अनुच्छेद के तहत दी गई स्वतंत्रता तेज आवाज में लाउडस्पीकर बजाने या अन्य प्रकार का ध्वनि प्रदूषण करने की अनुमति नहीं देता , राज्य इसे नियंत्रित कर सकता है । भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है इसलिए संविधान निर्माताओं ने लोक कल्याण के लिए राज्य अथवा सत्तासीन लोगों के लिए कुछ नीति निर्देशक तत्व बतलाए हैं। संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक उल्लिखित नीति निर्देशक तत्व बाध्यकारी नहीं है ,लेकिन कोई भी सरकार इनकी उपेक्षा नहीं कर सकता ।क्योंकि हर पांचवें वर्ष उसे जनता को मुंह तो दिखाना होता है ।संविधान के अनुच्छेद 47,48 एवं 48 ( )में पर्यावरण संबंधी बातें शामिल हैं। अनुच्छेद 47 में लोगों के पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य सुधार करना राज्य का कर्तव्य बतलाया गया है। अनुच्छेद48 में यह उल्लेख है कि राज्यकृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों .....शेष पेज 3 पर

एक साल में बड़ा सबक दे गया कोरोना

आज से ठीक एक साल पहले, जनवरी के अंत अंत में 2020 को, चीन ने जब वुहान शहर में तालाबंदी लागू की थी, तब पहली बार पूरी दुनिया ने कोरोना को एक महामारी की रूप में गंभीरता से लिया था।

साल भर बाद आज कोविड-19 न सिर्फ पूरी दुनिया में ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा चुका है, बल्कि इस ग्रह पर लगभग सभी की ज़िन्दगी को भी बदल चुका है। इस महामारी ने विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया है और पुराने सभी मानदंडों को भी चुनौती भी दे दी है। इस वैश्विक महामारी ने जलवायु परिवर्तन के साथ मिल कर एक यौगिक संकट उत्पन्न कर दिया है। साथ ही प्रकृति के साथ मानव विकास को संरेखित करने की आवश्यकता की याद दिला दी है, जो आने वाले वर्ष के लिए नई उम्मीदें प्रदान करता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम को-विड 19 से सबक सीखें और साथ ही आगे के वर्ष में उन चुनौतियों का समाधान करने की ओर आगे बढ़े। इस पूरे घटनाक्रम की कुछ मुख्य बातों की पहचान की गई है। दुनिया को एक साथ दो संकटों का समाधान करना है। जूनोटिक रोग, जैसे कोविड-19, और जलवायु परिवर्तन आपस में जुड़े हुए वैश्विक खतरे हैं। महामारी के बीच जलवायु संकट की निरंतर तीव्रता दुनिया भर में महसूस की जा रहा है। अच्छी बात ये है कि इस खतरे से बचने के तरीके काफ़ी मिलते जुलते हैं इसलिए इनका एक साथ समाधान करना संभव भी है।

सीखने को मिले कुछ एहम सबक

कोविड-19 के नाश के बावजूद, दुनिया भर के लोगों ने एक दूसरे और समाज की रक्षा के लिए एक साथ काम किया। महामारी ने एक लचीला समाज और अर्थव्यवस्था के निर्माण की तत्परता को उजागर किया, जहां मानव गतिविधियों को स्थायी लक्ष्यों के साथ संरेखित किया जाता है।

एकीकृत प्रणाली ज़रूरी

हमें संकटों से निपटने के लिए एकीकृत और प्रणालीगत बदलाव की आवश्यकता है। दोनों जलवायु और कोविड-19 संकटों ने अंतर्राष्ट्रीय असमानता पर प्रकाश डाला है।

ग्रीन रिकवरी बेहद ज़रूरी

हालांकि आशा के संकेत हैं, हमें एक समान ग्रीन रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए और अधिक करने की आवश्यकता है। कोविड-19 ने एक बार फिर खुलासा किया है कि प्रकृति, मनुष्य और दुनिया परस्पर जुड़े हुए हैं। जूनोटिक रोग, जैसे को-विड-19 और जलवायु परिवर्तन आपस में जुड़े हुए अंतर वैश्विक खतरे हैं और कुछ समान तरह के उपचार साझा करते हैं। प्रतिक्रियाओं को संरेखित करना सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने, एक स्थायी आर्थिक भविष्य बनाने और ग्रह के शेष प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता की बेहतर रक्षा करने का अवसर प्रस्तुत करता है।

महामारी ने लोगों को शहरों और परिवहन प्रणालियों को फिर से संगठित करने और रहने, काम करने और यात्रा करने के तरीके को बदलने का मौका दिया है। दुनिया भर में लोगों ने बाइक लेन को फिर से डिजाइन करने और स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं का समर्थन करने के लिए एक साथ काम किया है। साथ ही सरकार उन अवरोधों के माध्यम से तोड़ने में सक्षम साबित हुई है जो पहले अनिर्दिष्ट थे। कोविड-19 महामारी के बावजूद, रिन्यूएबल ऊर्जा ने उच्च प्रदर्शन दिखाया है। 2020 की पहली छमाही में यूरोपीय संघ में जीवाश्म ईंधन स्रोतों की तुलना में रिन्यूएबल स्रोतों ने पहले बार अधिक बिजली उत्पन्न की। कोयले से चलने वाले बिजलीघरों का विश्व का बेड़ा भी पहली बार 2020 में सिकुड़ गया है। पीक तेल की मांग भी शायद पहले ही गुज़र चुकी है।

महामारी ने असमानता के मुद्दे को संबोधित करने की आवश्यकता को भी क़रीब लाया है। समाज के सभी स्तंभों से लोग और नेता व्यवस्था परिवर्तन का आह्वान कर रहें हैं। कई संस्थानों और विचारशील नेताओं ने प्रकृति की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए सतत विकास के मार्गों को फिर से तैयार करने के लिए रास्ते प्रस्तावित किए हैं।

अंतिम लेकिन जरूरी बात है कि वर्तमान ग्रीन रिकवरी न तो पर्याप्त रूप से बड़ी है और न ही पर्याप्त महत्वाकांक्षी है। हम अभी भी तेज उत्सर्जन वृद्धि के मनसूबे में हैं। ग्रीन रिकवरी प्रत्येक देश की कोविड -19 आर्थिक नीति का केंद्र होना चाहिए। औद्योगिक देशों की वसूली योजना की 'ग्रीननेस' ('ग्रीन क्षमता') एक मिश्रित तस्वीर दिखती है जिसमें ग्रीन निवेश के संभावित लाभों को कम करके आंका गया है। कोविड-19 से पहले की नीतियों के आधार पर, 2030 में एक ग्रीन रिकवरी ग्रीनहाउस उत्सर्जन में 25% की कटौती कर सकती है।

सभी झारखंड वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनायें

रथिन भद्रा

Ph.- 8709167691

ग्रीन रिवोल्ट
हरित-नीरा रहे वसुंधरा

तेंदुए को मार कर खा गये केरल में आदमी हैं या दरिंदे?

सुदूर दक्षिण का सबसे शिक्षित राज्य केरल से एक हतप्रभ करने वाली खबर है। केरल के इडुक्की जिले ने मानवता को शर्मसार कर दिया है। चौकाने वाली घटना में इडुक्की जिले के एक गांव में पांच लोगों द्वारा एक 6 साल के तेंदुए को मारकर उसका मांस खाने का मामला सामने आया है। इस अपराध में शामिल पांचों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

ऐसा नहीं है कि केरल में पहली बार जानवरों के साथ ऐसी दरिंदगी का यह मामला है। केरलवासी पहले भी पशु पक्षियों के साथ अपनी दरिंदगी के लिये कुख्यात रहे हैं? वहां बार - बार ऐसी घटनायें होती रहती हैं।

याद किजिये केरल में पिछले साल भी एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जब एक गर्भवती हथिनी की पटाखों से भरा अनानास खाने से मौत हो गई थी। तब इस मामले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया था। तब दरिंदों ने अनानास में बम रख कर एक गर्भवती हथिनी को खाने के लिये दे दिया था। और बम उसके पेट में चला गया। वह पीड़ा और जलन से बचने के लिये घंटो एक तालाब में खड़ी रही थी और अंततः उसकी तड़प तड़प कर मौत हो गयी थी।

उसके पहले वहां एक बिल्ली को फांसी देकर उसकी तस्वीर सोशल मीडिया में डाल दी गयी थी। वहां के लोग स्ट्रीट डॉग को बेरहमी से मौत के घाट उतार देते हैं। पशुपालक सरकार से किसी विरोध में अपने जानवरों के साथ सड़क पर उतर आते हैं और विरोध प्रदर्शन में जानवरों की मौत हो जाती है। एक सबसे पढे लिखे राज्य के लोगों का यह हिंसक और क्रूरतम बर्ताव समझ से परे हैं।

परशुराम की यह भूमि देवभूमि भी कहलाती है। अपनी खुबसूरती और शांति की घाटी के लिये जाना जाने वाला केरल हकीकत में तो लगता है पशु पक्षियों, जीवों के लिये नर्क के समान है।

केरल में कुटीपाई नाम से अजन्मे बकरे के बच्चे के मांस को खाने का भी प्रचलन है। इस तरह के मांस के लिये गर्भवती बकरी का काटा जाता है। दलील है कि अजन्मे बकरे के बच्चे का मांस बहुत मुलायम होता है और मेहमानों को इसका व्यजंण खिलाने पर उन्हें चबाने में ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती।

जानी मानी राजनीतिज्ञ और पशु अधिकारों की संरक्षक मेनका गांधी ने स्वयं कहा है कि केरल के कई जिलों में जीव जंतुओं के प्रति लोगों का व्यवहार अति क्रूर है और वो सिर्फ मजाक-मजाक में ही कुत्तों, बिल्लियों की हत्या कर देते हैं। मेनका गांधी के बातों में सच्चाई भी नजर आती है। गर्भवती हथिनी की फल में बम लगा कर हत्या हो या एक भूखे भिखारी की एक मुट्ठी चावल करने पर पेड़ से बांध कर पीट - पीट कर हत्या ये सभी केरलवासियों के शिक्षित होने पर धब्बे के समान है।

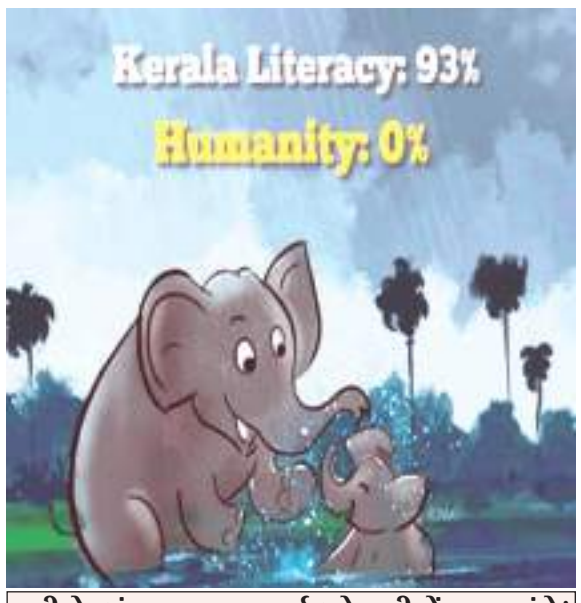

सदी के अंत तक 572 हवाई अड्डे पानी में डूब जाएंगे!

जलवायु परिवर्तन के चलते दुनिया भर के करीब 269 हवाई अड्डों पर डूब जाने का खतरा मंडरा रहा है वहीं यदि जलवायु परिवर्तन की रोकथाम पर ध्यान न दिया गया तो सदी के अंत तक यह खतरा बढ़कर 572 हवाई अड्डों को अपनी गिरफ्त में ले लेगो यह जानकारी न्यूकैसल विश्वविद्यालय द्वारा किए एक शोध में सामने आई है इस अध्ययन में शोधकर्ताओं ने जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के जलस्तर में होने वाली वृद्धि और उसके जहाजों के उड़ान मार्गों पर पड़ने वाले असर को समझने का प्रयास किया है

इसे समझने के लिए शोधकर्ताओं ने 14,000 से ज्यादा हवाई अड्डों सम्बन्धी आंकड़ों, जलवायु परिवर्तन और समुद्र के बढ़ते जल स्तर के प्रभाव का विश्लेषण किया है यह शोध जर्नल क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट में प्रकाशित हुआ है पता चला है कि यदि तापमान में हो रही वृद्धि 2 डिग्री सेल्सियस को पार कर जाएगी तो 100 से भी ज्यादा हवाई अड्डे औसत समुद्र तल से नीचे होंगे। तापमान में इतनी वृद्धि से 364 हवाई अड्डे पानी में डूब जाएंगे यदि इसके बाद भी तापमान में वृद्धि जारी रहती है तो सदी के अंत तक 572 हवाई अड्डे बाढ़ का शिकार बन जाएंगे। शोधकर्ताओं ने बढ़ते समुद्री जल स्तर और उसके हवाई अड्डों पर पड़ने वाले असर के आधार पर एक वैश्विक रैंकिंग भी तैयार की है जिसमें बताया गया है कि किन हवाई अड्डों पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है इस रैंकिंग के अनुसार यदि तापमान में वृद्धि वर्तमान दर पर जारी रहती है तो बैंकाक का सुवर्णभूमि हवाई अड्डे पर सबसे ज्यादा खतरा है जबकि यदि आरसीपी 8 .5+ की बात करने तो शंघाई पुडोंग हवाई अड्डा सबसे ज्यादा खतरे में है।

शोध के अनुसार यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ओशिनिया के सबसे ज्यादा हवाई अड्डों पर जलवायु परिवर्तन का खतरा है वहीं यदी खतरे में पड़े 20 प्रमुख हवाई अड्डों की बात करें तो उनमें पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया के हवाई अड्डों पर खतरा कहीं ज्यादा है इनमें चीन प्रमुख है। इस शोध से जुड़े प्रमुख शोधकर्ता रिचर्ड डॉसन की मानें तो तटीय क्षेत्रों के यह हवाई अड्डे एयरलाइन नेटवर्क के लिए बहुत मायने रखते हैं जिनके पानी में डूबने से सदी के अंत तक 10 से 20 फीसदी हवाई मार्गों पर इसका असर पड़ेगा।

जलवायु जोखिम के शीर्ष दस देशों में शामिल भारत

हमारे आपके समाज में आज भी ऐसे तमाम लोग हैं जो जलवायु परिवर्तन को अपनी समस्या नहीं मानते और किसी दूर देश की परेशानी समझते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए आज जारी क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स यक़ीनन हैरान करने वाला होगा। यह इंडेक्स बताता है कि जलवायु परिवर्तन को ले कर कौन सा देश कितने ख़तरे में है। तो बात जब जलवायु परिवर्तन की वजह से उपजे ख़तरों की हो तो आपको जान कर हैरानी होगी कि इन ख़तरों के मामले में भारत दुनिया के शीर्ष दस देशों में शामिल है।

भारत जलवायु जोखिम सूचकांक की सातवीं पायदान पर है और मोज़ाम्बिक यहाँ शीर्ष पर है। भारत के ऊपर हैं ज़िम्बाब्वे, जापान, और मलावी जैसे देश। शीर्ष के पांच देशों में तीन अफ़्रीका से हैं। जहाँ मोज़ाम्बीक, ज़िम्बाब्वे और बहामास को भारी तूफानों और उनके सीधे प्रभाव ने 2019 में सबसे ज़्यादा चोट पहुंचाई, वहीं पुएर्तो रिको, म्यांमार और हैती में 2000 - 2019 की अवधि में सबसे अधिक मौसम संबंधी नुकसान हुआ।

विकासशील देशों में कमज़ोर लोग/समूह तूफान, बाढ़ और गर्मी की लहरों जैसी चरम मौसम की घटनाओं से सबसे अधिक पीड़ित होते हैं, जबकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव दुनिया भर में दिखाई देते हैं। दक्षिण-पश्चिम हिंद महासागर में सबसे घातक और महंगे उष्णकटिबंधीय चक्रवात, इडाई, को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस द्वारा "अफ्रीका के इतिहास में सबसे खराब मौसम से संबंधित तबाही में से एक" करार दिया गया। इसने विनाशकारी क्षति और मानवीय संकट पैदा किया, जिससे मोज़ाम्बीक और ज़िम्बाब्वे, 2019 में, दो सबसे अधिक प्रभावित देश रहे। तूफान डोरियन की तबाही के उपरांत बहामास तीसरे स्थान पर है। पिछले 20 वर्षों (2000 - 2019) में, पुएर्टो रीको, म्यांमार और हैती ऐसे मौसम की घटनाओं के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित देश थे। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 (वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2021) के कुछ मुख्य नतीजे आज अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अडाप्टेशन शिखर सम्मेलन शुरू होने से कुछ घंटे पहले, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मनवॉच द्वारा प्रकाशित किए गए हैं।

भारत का इस सूचकांक में जगह बनाने पर भारती इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी के रिसर्च डायरेक्टर और एडजंक्ट एसोसिएट प्रोफेसर, (आईपीसीसी) की महासागरों और क्रायोस्फीयर पर विशेष रिपोर्ट के कोऑर्डिनेटिंग लीड (प्रमुख) लेखक, और IPCC की छठी मूल्यांकन रिपोर्ट के वर्किंग ग्रुप 2 में लीड लेखक, डॉ.अंजल प्रकाश, कहते हैं, ''यह जानना आश्चर्यजनक नहीं है कि भारत 2021 के वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक में शीर्ष 10 सबसे प्रभावित देशों में शामिल है। भारत पारिस्थितिकीय विविधता से धन्य है - ग्लेशियर, ऊंचे पहाड़, लंबी तटरेखा और साथ ही बड़े पैमाने पर अर्ध-शुष्क क्षेत्र जो जलवायु परिवर्तन के लिए आकर्षण का केंद्र हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से चक्रवातों की आवृत्ति में वृद्धि, ग्लेशियरों के पिघलने की गति में तेज़ी, और हीटवेव हो रहें हैं।'' वो आगे कहते हैं, ''अधिकांश भारतीय आबादी कृषि पर निर्भर है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इस वर्ष, भारत ने अपने कई शहरों को मानसून प्रणाली की परिवर्तनशीलता के कारण डूबते देखा। क्ढउउ रिपोर्ट सहित कई वैश्विक रिपोर्टें साल दर साल इस ओर इशारा करती रहीं हैं। अपनी बात को विस्तार देते हुए डॉ प्रकाश एक सवाल उठाते हुए कहते हैं, ''अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के ख़िलाफ सरकार की प्रतिक्रिया की कमी क्या है? 2008 में एक राष्ट्रीय अडॉप्टेशन योजना तैयार की गई थी, जिसके बाद राज्य की योजनाएं बनाई गई थी। पर अधिकांश योजनाओं में संसाधनों की कमी है, इसलिए वे जिला विकास और आपदा जोखिम में कमी लाने की योजनाओं में एकीकृत हो जाती हैं। वो समय आ चूका है कि सरकार इस जानकारी का अधिक विभाजन करने के लिए भारत के राज्य / ज़िला विशिष्ट जलवायु-जोखिम मानचित्रों को आयोगित करती है ताकि यह समझ सकें कि किन क्षेत्रों पर औरों से ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।

इस सूचकांक पर जर्मनवाच के डेविड एकस्टीन कहते हैं, ''ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स से पता चलता है कि ग़रीब और कमज़ोर देश चरम मौसम की घटनाओं के परिणामों से निपटने में विशेष रूप से बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं। उन्हें वित्तीय और तकनीकी सहायता की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए, हाल के अध्ययनों से ये पता चलना कि, पहले, औद्योगिक राष्ट्रों द्वारा प्रतिज्ञा किया गया 100 बिलियन डॉलर प्रति वर्ष का लक्ष्य नहीं पहुँचा जाएगा, और दूसरा यह कि जलवायु अनुकूलन के लिए इसका केवल एक छोटा सा अनुपात प्रदान किया गया है। आज से शुरू होने वाले जलवायु अडाप्टेशन शिखर सम्मेलन को इन समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

2000 और 2019 के बीच सबसे अधिक प्रभावित दस देशों में से प्रति व्यक्ति कम या निम्न मध्यम आय वाले विकासशील देश हैं। जर्मनवाच की वेरा कुएन्ज़ेल बताती हैं, ''गरीब देशों को सबसे ज़्यादा हानि पहुँचती है क्योंकि वे खतरों के हानिकारक प्रभावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं और उनकी क्षमता कम होती है। हैती, फिलीपींस और पाकिस्तान जैसे देश बार-बार चरम मौसम की घटनाओं की चपेट में हैं और अगली घटना के होने से पहले उन्हें पूरी तरह से ठीक होने का समय नहीं मिलता है। इसलिए, उनके लचीलेपन को मजबूत करने के लिए, न केवल अडाप्टेशन को संबोधित करना चाहिए, बल्कि नुकसान और नुकसान से निपटने के लिए आवश्यक सहायता भी प्रदान करना चाहिए। 2000 से लगभग 480.000 लोग 11.000 से अधिक चरम मौसम की घटनाओं के परिणामस्वरूप मारे गए

पिछले 20 वर्षों में, वैश्विक रूप से लगभग 480.000 घातक परिणाम सीधे तौर से 11.000 से अधिक हुई चरम मौसम की घटनाओं से जुड़े थे। तूफान और उनके प्रत्यक्ष निहितार्थ - प्रेसिपीटशन (वर्षा, बर्फ़ आदि की पड़ी मात्रा), बाढ़ और भूस्खलन - 2019 में क्षति के प्रमुख कारण थे। 2019 में दस सबसे अधिक प्रभावित देशों में से छह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित थे। हाल के विज्ञान से अनुमानित है कि न केवल गंभीरता, बल्कि वैश्विक स्तर पर तापमान में वृद्धि के हर दसवें डिग्री के साथ गंभीर उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की संख्या में वृद्धि होगी।

बांग्लादेश इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से जलवायु वैज्ञानिक और जल और बाढ़ प्रबंधन संस्थान के निदेश-ाक, डॉ. एम. शाहजहां मोंडल, ने कहा, ''बांग्लादेश, अपने भूभौतिकीय स्थान की वजह से, हमेशा चरम मौसम की घटनाओं और जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील रहा है। हमारा देश हिमालयी क्षेत्र और तीन विशाल नदियों (पद्मा, जिसे भारत में गंगा कहा जाता है, मेघना और जमुना) के नीचें बहाव की ओर में है, जो मानसून के मौसम में उत्तर की ओर से सभी बाढ़ के पानी को नीचे ले आतें है, जिससे विनाशकारी बाढ़ आती है। आपकी जानकारी के लिए बताते चलें कि जर्मनवॉच सालाना ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की गणना के लिए म्यूनिख रे पुनर्बीमा कंपनी की नैटकैटसर्विस डाटाबेस और अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष (क्यू) के सामाजिक-आर्थिक आंकड़ों से अपना डेटा प्राप्त करता है। भले ही बढ़ते नुकसान और घातकताओं का मूल्यांकन इन घटनाओं पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव पर सरल निष्कर्ष की अनुमति नहीं देता है, यह भारी आपदाओं की वृद्धि को दर्शाता है और राज्यों और क्षेत्रों की प्रभावितता का एक अच्छा अनुमान देता है। 2006 से 2019 तक जर्मनवॉच ने वार्षिक संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन (सीओपी/कौप) में सूचकांक प्रस्तुत किया है, सीओपी/कौप 26 के स्थगन के कारण इस बार सूचकांक को जलवायु अडाप्टेशन शिखर सम्मेलन से ठीक पहले प्रकाशित किया गया है।

जलवायु परिवर्तन की शामत लाएगी वाइट हाउस में बिडेन की आमद

एजेंसियां

तमाम ऐतिहासिक उठा-पटक के बाद, अमेरिका में, जो बिडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ ले ली है हालाँकि अभी उनका कार्यकाल औपचारिक रूप से शुरू भी नहीं हुआ था उससे पहले ही उनकी नीतियों और प्राथमिकताओं ने दुनिया भर की नज़रें उनकी और कर दी थीं।

ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी देश का चुनाव जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण जैसे गैर-सियासी मुद्दे पर लड़ा गया और जीता भी गया। जीता भी ऐसे कि किसी भी राष्ट्रपति पद के उम्मेदवार के मुक़ाबले सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त कर। राष्ट्रपति बिडेन ने इतिहास हर लिहाज़ से रच दिया है। यह तय है कि बिडेन न सिर्फ अमेरिका को पेरिस समझौते में फिर से शामिल कराने के अपने वादे को पूरा करेंगे, बल्कि यह भी साफ़ दिख रहा है कि पूरी दुनिया में जलवायु परिवर्तन से लड़ाई का नेतृत्व भी वो करने से चूकेंगे नहीं।

ऐसी उम्मीद है कि अब पद की शपथ लेने के बाद, जल्द ही, वो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जलवायु कार्रवाई पर कुछ घोषणाएं करेंगे। प्रमुख तौर पर 2035 तक बिजली क्षेत्र को कार्बन को शून्य करने के लिए बिडेन की प्रतिज्ञा से संबंधित संभावित शुरुआती बयान अपेक्षित हैं। साथ ही, कार ईंधन दक्षता, बिजली संयंत्र उत्सर्जन, और मीथेन पर ओबामा-युग के मानकों को बहाल करने के लिए कदम; किगली संशोधन में शामिल होने के अमेरिकी इरादे का संकेत और स्पष्ट निर्देश कि जलवायु एक शीर्ष विदेश नीति प्राथमिकता अपेक्षित है।

संयुक्त राज्य अमेरिका - विदेशी निवेश, व्यापार संबंधों, विकास सहायता, कूटनीति, नियमों और निगमों के माध्यम से - जीवाश्म ईंधन के विस्तार से संबंधित परियोजनाओं की एक श्रृंखला में शामिल है, साथ ही निम्नलिखित महत्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रणालियों के संरक्षण या विनाश को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

• अर्जेंटीना: वाका मुएर्ता - अमेरिका अंतरराष्ट्रीय विकास वित्तपोषण के माध्यम से अर्जेंटीना में फ्रैकिंग और तेल और गैस उत्पादन को प्रोत्साहित करता है, जो पिछली बार वाका मुएर्ता परियोजनाओं के लिए हुआ। उपराष्ट्रपति-निर्वाचित कमला हैरिस सहित कई अमेरिकी सीनेटरों ने इसके खिलाफ एक याचिका पर हस्ताक्षर किए। बिडेन स्वच्छ ऊर्जा का समर्थन करने के लिए संघीय विकास एजेंसियों को निर्देशित कर सकते हैं।

• कनाडा: टार सैंड्स - बिडेन ने कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन के खिलाफ बात की है, यह कहते हुए कि "टार सैंड्स की हमें ज़रूरत नहीं है।" बिडेन के राष्ट्रपति अभियान का एक प्रमुख वादा कीस्टोन एक्सएल को रद्द करने की प्रतिबद्धता थी। वह मिनेसोटा के माध्यम से अमेरिका में कनाडाई टार रेत लाने के लिए एक नई परियोजना, प्रस्तावित लाइन 3 पाइपलाइन जो विपक्ष में बढ़ रही है, को भी रोक सकतें हैं।

• ब्राजील: अमेज़ॉन विनाश - बिडेन ने कहा है कि वह वनों की कटाई के लिए ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो को जवाबदेह ठहराएंगे। अन्य देशों को रैली करने के माध्यम से अमेज़न सुरक्षा करने के लिए $ 20 बिलियन के समर्थन से शायद यह हासिल किया जा सकता है। हालांकि स्थानीय ब्राज़ीलियाई समूहो इस बात पर ज़ोर डालते हैं कि यह इस तरह से किया जाना चाहिए जो ब्राजील की अमेज़ॅन के अपने हिस्से पर संप्रभुता को स्वीकार करता है और उसका सम्मान करता है।

इसके साथ, ऐसा संभव है कि 'क्लीन ग्रोथ फर्स्ट' के जुमले को तरजीह देते हुए बिडेन विदेशी जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के अमेरिकी समर्थन को सीमित कर दें। गौर करने वाली बात है कि 2010 - 2019 के बीच अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक ने विदेशी जीवाश्म ईंधन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 90% से अधिक का वित्त पोषण किया, और हाल ही में मोज़ाम्बिक एलएनजी परियोजना को 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान किया। बिडेन पहले ही संकेत दे चुके हैं कि वह विदेशी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को न सिर्फ खत्म कर देंगे बल्कि चीन सहित अन्य 20 देशों को ऐसा ही करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।

कुल मिलाकर, जो बिडेन की वाइट हाउस में आमद जलवायु परिवर्तन के खिलाफ दुनिया की लड़ाई में निर्णायक साबित होगी।

कोयला जलाना रोकना है जरूरी

एक वेबिनार में कहा गया कि नीले आसमान और साफ फेफड़ो के लिए कोयले को जलाए जाने से रोकना चाहिए। कोयला जलाए जाने के कारण खतरनाक पार्टिकुलेट मैटर, सल्फर डाई ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे खतरनाक प्रदूषित कण निकलते हैं। स्वच्छ कंबस्टन को इंसेटिव दिए जाने की जररूत है। साथ ही स्वच्छ तरीके से ऊर्जा पैदा किए जाने को भी प्राथमिकता में रखना होगा। बजट 2021 में इन चुनौतियों को शामिल किए जाने की आवश्यकता है।

सीएसई के इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन यूनिट के कार्यकम निदेशक निवित कुमार यादव ने कहा कि इंडस्ट्री यह मानती है कि नैचुरल गैस कंबस्टन के लिए ज्यादा प्रभावी, स्वच्छ, कम प्रबंधन लागत वाला और अन्य लागतों जैसे प्रदूषण नियंत्रण आदि के लिए ज्यादा बेहतर और आसान है। हालांकि मौजूदा ईंधन कीमतों के हिसाब से इसे अपनाना बेहद कठिन है। हमने दिल्ली में औद्योगिक क्षेत्रों में कोयले और गैस के इस्तेमाल की तुलना की है। मौजूदा समय में गैस ईंधन का इस्तेमाल उद्योगों को कोयला के मुकाबले एक से तीन गुना ज्यादा लागत में डालता है। ज्यादा कीमत वाले ईंधन की वजह से उद्योग राज्यों और देश में प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाते हैं।

वहीं, सुनीता नारायण ने कहा कि नैचुरल गैस को जीएसटी के पांच फीसदी वाले स्लैब में लाने की जरूरत है। साथ ही उद्योगों को बिजली आपूर्ति की लागत कम करने की जरूरत है।

स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल होगा कारगर

वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए उद्योगों के जरिए स्वच्छ ईंधन का इस्तेमाल बेहद कारगर रणनीति साबित हो सकती है। हालांकि, दिल्ली-एनसीआर में औद्योगिक ईकाइयों के जरिए बड़े पैमाने पर प्रदूषण के लिए प्रबल तरीके से जिम्मेदार कोयला ईंधन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसे में बजट-2021 में स्वच्छ ईंधन को यदि बढ़ावा दिया जाता है तो वायु प्रदूषण की लड़ाई न सिर्फ दिल्ली-एनसीआर के लिए बल्कि समूचे देश के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

सेंटर फॉर साइंस एंड एनवॉयरमेंट ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से बजट 2021 में स्वच्छ ईंधन को औद्योगिक इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहन देने के प्रावधान की अपील की है। सीएसई ने अपनी अपील में कहा है कि कोयला के मुकाबले उद्योगों को बिजली और प्राकृतिक गैस को इंसेटिव देकर प्रतिस्पर्धी बनाया जाना चाहिए। इस कदम से न सिर्फ दिल्ली और एनसीआर में बल्कि देशभर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी।

बेहतर बैटरी स्टोरेज रिन्युब्ल एनर्जी को कर सकता है और भी सस्ता

एजेंसियां

आज जारी एक ताज़ा विश्लेषण से पता चलता है कि अगर रिन्युब्ल एनेर्जी उत्पादन में ऊर्जा के भंडारण को बेहतर कर लिया जाये तो थर्मल पावर, या कोयले से बनी बिजली, के मुक़ाबले हरित ऊर्जा की प्रति यूनिट कीमत और भी कम हो सकती है।

यह रिपोर्ट बताती है कि एक अगर एक काल्पनिक हाइब्रिड (सौर+पवन और लीथियम-आयन बैटरी भंडारण) ऊर्जा उत्पादन सिस्टम बनाया जाये तो आने वाले दस सालों में कोयला बिजली की तुलना में प्रति यूनिट बिजली की कीमत में लगभग 31 प्रतिशत की गिरावट अपेक्षित है।

फ़िलहाल, साल 2021 में, जहाँ इस हाइब्रिड सिस्टम से बनी बिजली की कीमत रु 4.97 kWh है, वो 2030 तक गिरकर रु 3.4 kWhतक आ जाएगी। अगर तुलना की जाए तो तमिलनाडु में कोयला बिजली संयंत्रों से उत्पादित बिजली की लागत अभी रु 4.5 से रु 6 kWh के बीच आती है। इस 1 गीगा वाट की हाइब्रिड प्रणाली से यह

कीमत तब है जब 2021 में कुल 2 घंटे का ही बैटरी स्टोरेज माना जा रहा है। इस बैकअप को चरणबद्ध तरीके से 2030 तक 4 घंटे कर लिया जायेगा और तब अच्छी ख़ासी बचत हो पायेगी। इस शोध में आगे कहा गया है कि लिथियम आधारित बैटरी स्टोरेज की मदद से, स्टोरेज की कमी के चलते, उत्पादन को अपेक्षित स्तर से कम करने वाली स्थिति से भी बचा जा सकता है। इस स्थिति को कर्टेलमेंट कहते हैं। तमिल नाडु में तो लॉक डाउन के दौरान लगभग पचास प्रतिशत सोलर पावर प्लांट्स में कर्टेलमेंट करना पड़ा। ऐसे ही, साल 2019 में, पवन ऊर्जा उत्पादन में भी कर्टेलमेंट करना पड़ा। जहाँ साल 2018 में दिन भर में 1.87 घंटे का कर्टेलमेंट हो रहा था, वो अगले साल, 2019 में बढ़ कर 3.52 घंटे प्रति दिन हो गया। यह विश्लेषण क्लाइमेट ट्रेंड्स और JMK रिसर्च के साझा प्रयास से पूरा हुआ है। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए JMK रिसर्च की संस्थापक ज्योति गुलिया कहती हैं, ''हमारे विश्लेषण ने पाया कि इस हाइब्रिड रेन्युब्ल एनेर्जी सिस्टम में बिजली की लागत फ़िलहाल नए कोयला संयंत्रो से बनी बिजली के लगभग बराबर ही है, लेकिन आने वाले समय में बेहतर बैटरी स्टोरेज से यह कीमतें 31 फीसद तक कम हो जाएँगी।''

क्लाइमेट ट्रेंड्स और जेएमके रिसर्च एंड एनालिटिक्स द्वारा जारी किया गया विश्लेषण में इस हाइब्रिड सिस्टम में 500MWh के स्टोरेज के साथ 800MWh सौर और 200MWh पवन की प्रारंभिक क्षमता को आधार बनाया गया है। इस हिसाब से ये सिस्टम 2023 तक तमिलनाडु की रोज़ाना २ घंटे की सालाना बिजली डिमांड पूरी कर लेगा। आगे, इसकी स्टोरेज क्षमता 2024-2026 के लिए तीन घंटे के दैनिक बैकअप के लिए संवर्धित है, और फिर 2027-2030 के लिए प्रति दिन 4 घंटे। अंतिम वर्ष में यह हाइब्रिड प्रणाली तमिलनाडू की कुल ऊर्जा मांग के 29 फीसद को पूरा करेगी और वो भी रु 3.4 kWhकी कीमत पर। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि अगले 3 सालों में तमिलनाडु में 5 नई थर्मल पावर परियोजनाएं हैं।इनमें रु 5 - 6 / kWhप्रति यूनिट की दर से चेय्यूर अल्ट्रा मेगा कोयला बिजली संयंत्र इनमें से सबसे बड़ा है और इस हाइब्रिड मॉडल की उत्पादन कीमतों से 32 प्रतिशत से 43 प्रतिशत अधिक महंगा साबित होगा।

अपनी प्रतिक्रिया देते हुए क्लाइमेट ट्रेंड्स की निदेशिका, आरती खोसला कहती हैं, ''स्थापित अक्षय ऊर्जा क्षमता के मामले में तमिलनाडु देश में सबसे आगे है, लेकिन साथ ही, यहाँ कई बड़ी कोयला परियोजनाएं भी आने वाली हैं। ऐसे में जब इस विश्लेष्ण से साफ़ है कि बेहतर बैटरी स्टोरेज से रेन्युब्ल एनेर्जी और सस्ती साबित होगी, तभी नीति निर्माताओं को सोचना चाहिए कि क्या वाकई उन्हें कोयला बिजली को इतनी तरजीह देनी चाहिए।

अगर इस हाइब्रिड सिस्टम से उत्पादित बिजली देश की राजधानी दिल्ली भेजी जाये तो तमाम शुल्क देने के बाद भी यह 2030 में दिल्ली की 100 फीसद सालाना बिजली डिमांड पूरी कर देगी और वो भी रु 4.4/'हँ की कीमत पर।

द्वारा:Climate कहानी

राँची रेल मंडल द्वारा 10 कि.मी. की क्रॉस कंट्री रन का आयोजन

रांची :नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125 वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा घोषित "पराक्रम दिवस" के अवसर पर रेलवे सुरक्षा बल, रांची मंडल द्वारा 10 कि.मी. की क्रॉस कंट्री रन का आयोजन, हटिया रेलवे परिसर में मंडल सुरक्षा आयुक्त, रांची के नेतृत्व में की गई। मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर क्रॉस कंट्री रन का झंडा दिखाकर शुभारंभ किया। इस दौड़ में रेलवे सुरक्षा बल के विभिन्न इकाइयों से 78 अधिकारी व जवानों ने भाग लिया।

इस प्रतिस्पर्धा में पुरुष वर्ग में प्रथम स्थान रूप सिंह मीणा (आरक्षी, रेलवे सुरक्षा बल, मुरी) द्वितीय स्थान नीतीश कुमार (रेलवे सुरक्षा बल मुरी) तथा तृतीय स्थान संतोष कुमार (श्वान दस्ता मुरी) ने प्राप्त किया। महिलाओं के वर्ग में प्रथम स्थान सुश्री शारदा चौधरी, द्वितीय स्थान रानी सिंह एवं तृतीय स्थान ललिता कुमारी ने प्राप्त किया। फिटनेस का उदाहरण प्रस्तुत करने वाले श्वान दस्ता मूरी के 59 वर्षीय उप निरीक्षक श्री एम. उरांव को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु विशेष रुप से सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर अपर मंडल रेल प्रबंधक (परिचालन) एम एम पंडित, अपर मंडल रेल प्रबंधक (इंफ्रा) सतीश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक जी सी हैंब्रम, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवनीश, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी माणिक शंकर, वरिष्ठ मंडल सिग्नल एवं दू-रसंचार अभियंता एस उरांव एवं अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी उपस्थित रह कर जवानों का उत्साह बढ़ाया।

मुख्यमंत्री ने संतालपरगना को दी सौगात ग्रिड सब-स्टेशन की रखी आधारशिला

संवाददाता

बरहेट/रांची :साहिबगंज का बरहेट प्रखण्ड पिछड़े इलाके में आता है, तथा कई मूलभूत सुविधाएं इस क्षेत्र तक नहीं पहुँच सकी हैं। इसे देखते हुए सरकार ने क्षेत्र के समग्र विकास के लिए समस्याओं को चिन्हित किया है। अब इस योजना के शिलान्यास से साहिबगंज में विधुत आपूर्ति में कोई बाधा नहीं होगी। साथ ही, बरहेट प्रखण्ड के किसी भी गांव में बिजली की कोई दिक्कत नहीं रहेगी। लंबे समय से बरहेट के लोग कई सरकार की योजनाओं के लिए आशान्वित होते रहें हैं। उसे पूरा किया जाएगा। संतालपरगना के जिन क्षेत्रों में विकास की योजनाएं नहीं पहुंची हैं, उसे कैसे पहुंचाया जाए। उसपर कार्य हो रहा है। बरहेट को अनुमंडल बनाने की दिशा में भी पुख्ता कार्य किया जा रहा है। ये बातें मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने कही। मुख्यमंत्री 132/33 केवी ग्रिड सब स्टेशन बरहेट-किताजोर (साहिबगंज) तथा 132 केवी पाकुड़-राजमहल (लिलो) संचरण लाइन के शिलान्यास समारोह में बोल रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य को आगे बढ़ाना है, विकास के पथ पर आगे लाना है तो सड़क, पानी और बिजली बेहद जरूरी है। विकास की नई रणनीति बनाई है । मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए झारखण्ड

सरकार ने कई योजनाओं के ज़रिए विकास की नई रणनीति बनाई है। 100 मेगावाट सब स्टेशन निर्माण की आधारशिला रखी गई है, जो करीब दो वर्ष में बन कर तैयार हो जाएगा। करीब पांच हजार किमी बिजली की लाइन बिछाई जाएगी। ताकि लोगों के घरों तक बिजली पहुंच सके। इन सब कार्यों की प्रगति रिपोर्ट पर सरकार की नजर रहेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राशन कार्ड से वंचित लोगों को हरा राशन कार्ड प्रदान करने का कार्य सरकार कर रही है। पेंशन योजना का लाभ करीब छः लाख जरूरतमंदों को दिया जा रहा है। धोती-साड़ी योजना का लाभ जल्द राज्यवासियों को मिलेगा। हम राज्य में बदलाव लाने को तैयार हैं। कोरोना संक्रमण का धुंध छटने के साथ ही बदलाव भी नजर आयेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार लगातार कोरोना वायरस अपना चेहरा बदल रहा है, उसमें हम सभी को और भी सुरक्षित रहने की ज़रूरत है। कई पाबंदियां हैं। स्कूल और कॉलेज बंद हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर ज़िले में मॉडल विद्यालय शुरू करने के साथ-साथ पहली से 12वीं कक्षा तक सीबीएसई की पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई गई है। क्योंकि अगर राज्य के बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है तो उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना होगा।

इनका हुआ शिलान्यास एवं उद्घाटन

- पतना हिरणपुर के छह किलोमीटर में गुमानी नदी पर उच्चस्तरीय पुल निर्माण का शिलान्यास।
- तकनीकी सुविधाओं से लैस मॉडल स्कूल बरहेट साहिबगंज का ऑनलाइन उद्घाटन एवं कस्तूरवा गांधी बालिका उच्च विद्यालय भवन बरहेट का उद्घाटन।
- साहिबगंज तथा गोड्डा अंतर्गत विभिन्न विकास योजना का भी मुख्यमंत्री ने उद्घाटन तथा शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, वन पट्टा, कृषि ऋण, कन्यादान योजना, प्रधानी पट्टा, वृद्धा पेंशन योजना, ग्रीन राशन कार्ड योजना, जेएसएलपीएस अन्तर्गत कैश लोन लिंकेज, सामुदायिक वन अधिकार पट्टा एवं फूलो-झानो योजना के तहत लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया गया।

कोल इंडिया के एनसीएल,सीसीएल और डब्ल्यूसीएल को कोयला मंत्री अवॉर्ड

संवाददाता

केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बृहस्पतिवार को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में कोल इंडिया लिमिटेड (सीआ-ईएल) की तीन अनुषंगी कंपनियों- नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) और वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) को ''कोयला मंत्री अवॉर्ड'' प्रदान किए। देश में कोयला खनन में सर्वश्रेष्ठ और सतत प्रणालियों (सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस) को बढ़ावा देने के लिए ये अवॉर्ड शुरू किए गए हैं। कार्यक्रम में श्री जोशी ने सीआईएल के एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) - 'प्रोजेक्ट पैशन' का भी शुभारंभ किया, जिससे कंपनी के व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार और बढ़ी हुई आंकड़ा शुचिता (एनहैन्स्ड डेटा इन्टेग्रिटी) से कंपनी की प्रगति में मदद मिलेगी।

केंद्रीय कोयला मंत्री श्री प्रल्हाद जोशी ने कोल इंडिया लिमिटेड के ईआरपी का भी किया शुभारंभ

एनसीएल को कोयला उत्पादन और उत्पादकता में शानदार प्रदर्शन करने के लिए अवॉर्ड दिया गया, जबकि सीसीएल और डब्ल्यूसीएल ने क्रमशः सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा प्रणालियों को अपनाने और सतत खनन (सस्टेनेबल माइनिंग) के लिए अवाड्र्स हासिल किए। प्रल्हाद जोशी ने कहा कि कोयला भारत की ऊर्जा आकांक्षाओं की लाइफलाइन है और रहेगा। भारत सेफ्टी (संरक्षा) और सस्टेनेबिलिटी (सतत विकास) के सभी मानकों के पालन के साथ कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहा है। इन मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए ही ये अवाड्र्स शुरू किए गए हैं। मैं सभी विजेताओं को बधाई देता हूं तथा मेरा विश्वास है कि आने वाले समय में कोयला कंपनियां उत्पादकता, सेफ्टी एवं सस्टेनेबल माइनिंग के और भी ऊंचे मानदंड स्थापित करेंगी।

रोटरी क्लब ने फ्लोरेंस बारला की मदद की

रांची :23जनवरी को रोटरी रांची साउथ के अध्यक्ष रथीन भद्रा ने इंटरनॅशनल एथेलीट फ्लोरेंस बरला (जो कि गोल्ड मेडलिस्ट है इंटरनेशनल मीट का और झारखंड की एक मात्र महिला रनिंग में भारत को दो गोल्ड मेडल इंटरनेशनल मिट में दिलाया) की परेशानियों के बारे में समाज सेवक श्री सुवेन्दु भट्टा दा के कहने पर संज्ञान लेते हुए आज फ्लोरेंस बारला को खाद्य सामग्री रोटरी रांची साउथ के तरफ से दिया गया । रोटरी इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3250 के जोन 16 के अस्सिस्टेंट गवर्नर रोटेरियन मुकेश तनेजा जी ने फ्लोरेंस बारला और उनके कोच भाटिया जी को आश्वस्त किया कि वे बेझिजक रोटरी से संपर्क कर सकते है । रोटेरियन सुभाष कुमार (प्रिंसिपल टौरियण वर्ल्ड स्कूल) ने फ्लोरेंस बारला को रोटरी रांची साउथ के तरफ से स्मृति चिन्ह दे कर सम्मानित किया और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी ।उपाध्यक्ष

रोटेरियन सुमित दास और रोटेरियन स्पाउस पिंकी तिग्गा (डायरेक्टर ओरायन्स स्कूल) ने फ्लोरेन्स को शुभकामनाएं दी ।

फ्लोरेंस बारला और उनकी बहन आशा बारला के पैतृक आवास गुमला के गांव में है और उनकी स्थिति ठीक नही है ये बड़ी ही विडंबना है कि भारत को गोल्ड दिलाने वाली और नेशनल रेकॉर्ड होल्डर इतने बेहतरीन झारखंड के प्रतिभाओ के घर पर एक शौचालय भी नही है और उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, इस बात का भी संज्ञान लेते हुए रोटरी रांची साउथ के अध्यक्ष रथीन भद्रा ने सभी मेंबर्स के अनुमति से और अस्सिस्टेंट गवर्नर मुकेश तनेजा के परमिशन से फ्लोरेंस बारला और आशा बारला के पैतृक आवास में रोटरी के तरफ से शौचालय बनाने का प्रस्ताव रखा और सभी मोजूद रोटेरियन ने इसेपास किया तथा 11000/- की एक अग्रिम राशि सोचालय निर्माण के लिए देना का ऐलान किया और फ्लोरेंस बारला के कोच को सोचालय निर्माण का एक एस्टीमेट किसी भी ठेकेदार से कर रोटरी रांची साउथ को देने का आग्रह किया। श्री सुवेन्दु भटा जी ने भी सोचालय निर्माण में अपना पर्सनल कॉन्ट्रिब्यूशन देने का ऐलान किया ।रोटेरियन रथीन भद्रा ने सभी मेंबर्स की अनुमति लेते हुए श्री सुवेन्दु भट्टा जी को रोटरी का मपेल पिन असिस्टेंट गवर्नर द्वारा पहना कर रोटरी रांची साउथ का मेंबर बनाया गया ।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जागरूकता अभियान

रांची : 25जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर रांची रेल मंडल के प्रमुख स्टेशनों, स्टेशन परिसरों तथा रेलवे कॉलनियों में पोस्टर तथा बैनर के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाया गया । ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करवाने एवं मतदान करने के लिए प्रेरित करने हेतु इस अभियान को चलाया गया तथा लोगो को जागरूक किया गया।

.....पेज एक का शेष

भारतीय संविधान और हमारा पर्यावरण

से संगठित करने का प्रयास करेगा और विशिष्टतया गायों और बछड़ों तथा अन्य दुधारू और वाहक पशुओं की नस्लों के परिरक्षण और सुधार के लिए और उनके वन का प्रतिषेध करने के लिए कदम उठाएगा। संविधान के 42वें संशोधन द्वारा जोड़ें गए अनुच्छेद48(a) के अनुसार राज्य ,देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा वन्य प्राणियों की रक्षा करने का प्रयास करेगा ।

संविधान में नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं जो 1976 में 42वें संशोधन द्वारा A अनुच्छेद 51 (a)में रखे गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के प्रति भारतीय नागरिकों को संविधान का अनुच्छेद 51(a)(g)कहता है कि तालाब, नदियां , वन्यजीव सहित सभी तरह की प्राकृतिक पर्यावरण संबंधित चीजों की रक्षा करना और उनको बढ़ावा देना हर भारतीय का कर्तव्य होगा ।साथ ही प्रत्येक नागरिक को सभी जीवो के प्रति करुणा रखनी होगी।

आज जब हम अपने संविधान और गणतंत्र की 72 वीं वर्षगांठ मना रहे हैं अपने अधिकारों और कर्तव्यों का आभास अवश्य होना चाहिए।

संजय सेठ ने दो नये लिफ्टों का किया उद्घाटन

संवाददाता

रांची रेल मंडल यात्रियों की सुविधा के लिए हमेशा तत्पर है, इसी कड़ी में रांची लोकसभा क्षेत्र के सांसद संजय सेठ द्वारा हटिया स्टेशन पर नवनिर्मित दो लिफ्ट का उद्घाटन किया गया । सांसद ने मंडल रेल प्रबंधक नीरज अम्बष्ठ के साथ हटिया स्टेशन पर उपलब्ध अन्य यात्री सुविधाओं को भी देखा। हटिया रेलवे स्टेशन पर एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए सीढ़ी, रैम्प, एस्केलेटर की सुविधा पहले से ही थी, अब लिफ्ट लग जाने से एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने के लिए यात्रियों को एक और अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों, दिव्यांग तथा बीमार यात्रियों को अब एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म जाने में काफी सहूलियत होगी। नवनिर्मित लिफ्ट आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस है, इन लिफ्टों में ऑटोमेटिक रेस्क्यू डिवाइस, फायर अलार्म सिस्टम, अनाउंसमेंट सिस्टम तथा इंटरकॉम लगे हुए हैं ।

दोनों लिफ्ट के उद्घाटन के अवसर पर वरिष्ठ मंडल अभियंता (समन्वय) अमित कंचन, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी नीरज कुमार, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवनीश, वरिष्ठ मंडल विद्युत अभियंता (सामान्य) कुलदीप कुमार, मंडल वाणिज्य प्रबंधक डॉ देवराज बनर्जी तथा अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी हटिया स्टेशन पर उपस्थित थे।

नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति राँची की बैठक सम्पन्न

रांची : सीएमपीडीआई मुख्यालय, राँची में नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), राँची की बैठक का आयोजन एस. के. गोमास्ता, निदेशक (तकनीकी/सीआरडी) की अध्यक्षता में किया गया। इस बैठक में विशिष्ट अतिथि के रूप में निर्मल दुबे, सहायक निदेशक एवं कार्यालय अध्यक्ष, क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (पूर्व क्षेत्र), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जुड़े हुए थे। अपने अध्यक्षीय संबोधन में गोमास्ता ने भाषा के प्रयोग संबंधी हीन भावना को त्याग कर व्यावहारिक जीवन और कार्यालय के कार्यकलापों में राजभाषा के प्रयोग को बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही उन्होंने राजभाषा के कार्यान्वयन में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए विभिन्न उपक्रमों के बीच आपसी संपर्क को बढ़ाने और विभिन्न तकनीकी नवाचारों के प्रयोग का भी आह्वान किया। इस दौरान राँची नगर स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग पंद्रह उपक्रमों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा तथा राजभाषा कार्यान्वयन संबंधी विभिन्न सुझाव दिए।

सीएमपीडीआई के पहले ड्रोन का प्रदर्शन

संवाददाता रांची : आईआईसीएम परिसर में कोल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष प्रमोद अग्रवाल (भा0प्र0से0) के समक्ष सीएमपीडीआई के पहले ड्रोन का लाइव डिमोंसट्रेशन किया गया। इस मौके पर प्रमोद अग्रवाल ने ड्रोन के स्पेसिफिकेशन, एफीसियेंसी एवं तकनीकी पहलुओं से संबंधित विस्तृत जानकारी तथा इससे होने वाले लाभ के बारे में वार्ता की। इस अवसर पर उन्होंने इस क्षेत्र में सीएमपीडीआई द्वारा किए गए पहल की सराहना की।इस मौके पर सीएमपीडीआई के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एस0 सरन, सीसीएल के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक पी0एम0 प्रसाद, सीएमपीडीआई के निदेशक (तकनीकी/आरडीएंडटी) आर0 एन0 झा, निदेशक (तकनीकी/पीएंडडी) ए0के0 राणा, मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री सुमीत कुमार सिन्हा, कोल इंडिया के अध्यक्ष के तकनीकी सचिव एम0के0 सिंह तथा आईआईसीएम के कार्यपालक निदेशक पी0सी0 मिश्रा उपस्थित थे।

सीएमपीडीआई द्वाराड्रोनकाप्रयोगलिडा-रसेंसर के जरियेस्व-स्थान (इन सिटु) उत्खनन, ओवरबर्डेनडम्पतथाकोयलास्टॉक के मामलेमेंआयतनसंबंधी (वॉल्यूमेट्रिक) माप के लिए कियाजाएगा। लिडार सेंसर का उपयोग पेड़ों की ऊंचाई के आकलन

करने तथा वनस्पति का मूल्यांकन करने, भू-भाग की सटीक माप (टेरेन मैपिंग) आदि के लिए प्रयोग किया जा सकता है।

ड्रोन पर लगे थर्मल सेंसर (जिसकी आपूर्तिदूसरीईकाई के साथ की जाएगी)का उपयोग भूमिगत कोयला खानों में लगी आग की जगह का पता लगानेतथा भ्रंश/दरारका पता लगाने में किया जाएगा। ड्रोन आधारित सेंसर की सहायता से 20 से0मी0 रिजोल्यूशन थर्मल डाटा बनाना संभव हो जाएगा जो थर्मल अनोमली की मैपिंग के जरिए विद्यमान/उपस्थित भूमिगत कोयला खान की आग की जगह की सटीक पहचान करने में काफी सहायक हो सकता है। हा-इरिजोल्यूशन के ऑप्टिकल इमेज बनानेमेंऑनबोर्ड हाईरिजोल्यूशन ऑप्टिकल कैमरा का प्रयोग किया जाएगा जो वनाच्छादन अध्ययन सेटल मेंट मैपिंग तथा अन्य कई अनु प्रयोग के क्षेत्र के लिए ऑर्थो-फोटो मोजेक तैयार करने में काफी उपयोगी होगा।

जलवायु परिवर्तन के रोकथाम मेंअपने योगदान को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे हैं अमीर देश

एजेंसियां

दुनिया भर के तमाम विकसित देशों और संस्थानों ने 146,000 करोड़ रुपए को गलत तरीके से क्लाइमेट अडॉप्टेशन फण्ड का हिस्सा बताया है, जबकि उनका जलवायु अनुकूलन से कोई वास्ता नहीं था

दुनियाभर के तमाम विकसित देशों ने अपने द्वारा जलवायु की रोकथाम के लिए दी जा रही मदद को बढ़ा-चढ़ा कर पेश किया है इसके चलते जलवायु सम्बन्धी खतरों से निपटने के लिए करीब 146,000 करोड़ रुपए (2,000 करोड़ डॉलर) कम पड़ जाएंगे यह जानकारी केयर इंटरनेशनल द्वारा आज जरिए रिपोर्ट क्लाइमेट अडॉप्टेशन फाइनेंसः फैक्ट और फिक्शन में सामने आई है रिपोर्ट से यह भी पता चला है कि कई जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं में लिंग और गरीबी को शामिल करना केवल एक दिखावा है।

गौरतलब है कि 2015 में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए पैरिस समझौता हुआ थो जिसमें क्लाइमेट मिटिगेशन और अडॉप्टेशन पर समान रूप से जोर देने की बात कही गई थी इसी के चलते विकसित देशों ने 2020 तक हर साल जलवायु अनुकूलन के

लिए 365,022 करोड़ रुपए (5,000 करोड़ डॉलर) जुटाने का वादा किया थो लेकिन ओईसीडी द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि 2018 में जलवायु अनुकूलन के लिए 122,648 करोड़ रुपए (1,680 करोड़ डॉलर) का भुगतान किया था, पर केयर इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट से पता चला है कि वास्तव में यह आंक-ड़ें इससे काफी कम थे अनुमान है कि 2018 में केवल 70,814 करोड़ रुपए (970 करोड़ डॉलर) जुटाए गए थे। इस अध्ययन से जुड़े शोधकर्ता जॉन नोर्डबो ने बताया कि दुनिया का सबसे गरीब तबका जलवायु परिवर्तन का जिम्मेवार न होते हुए भी इसका सबसे ज्यादा परिणाम भुगत रहा है न केवल समृद्ध देश बल्कि ग्लोबल साउथ के भी कई देश जलवायु अनुकूलन की दिशा में योगदान करने में विफल रहे हैं इसके बावजूद वो ऐसा दिखा रहा हैं कि वो इस फण्ड में अपनी क्षमता से ज्यादा दे रहे हैं यह सचमुच शर्मनाक है इस अन्याय को जल्द दूर किया जाना चाहिऐ इस बाबत उनके द्वारा एक वास्तविक योजना प्रस्तुत करनी चाहिए, जिसमें वास्तविक रूप से धन दिया जाऐ जिससे उन्हें इसे दिखाने के लिए रिपोर्टिंग ट्रिक की मदद न लेनी पड़े ।

इसे समझने के लिए केयर इंटरनेशनल ने घाना, युगांडा, इथियोपिया, नेपाल, वियतनाम और फिलीपींस में अन्य सामाजिक संस्थानों की मदद ली है, और 112 परियोजनाओं का आंकलन किया है जोकि 2013-17 के बीच अनुकूलन के लिए किए गए कुल योगदान के 13 फीसदी हिस्से को दर्शाते हैं इससे पता चला है कि इन परियोजनाओं में अनुकूलन सम्बन्धी योगदान को 42 फीसदी बढ़ा कर दिखाया गया है यदि इस आधार पर देखें तो इस अवधि में करीब 146,000 करोड़ रुपए (2,000 करोड़ डॉलर) से अधिक की धनराशि को अडॉप्टेशन फण्ड के अंतर्गत बढ़ा कर दिखाया गया है

फोटो न्यूज

टीम ग्रीन की उपलब्धि

टीम ग्रीन के सदस्यों ने रांची में वृक्षारोपण का जो बीड़ा उठाया है उसका प्रतिफल उनके द्वारा लगाये गये पौधों को वृक्ष के रूप में बढते हुये देखा जा सकता है।

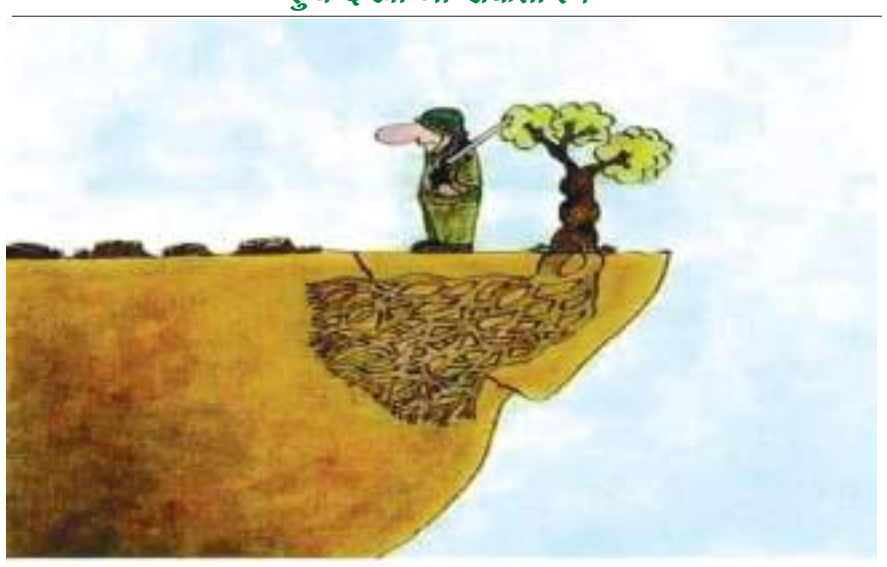

1990 से लुप्त हो गई मधुमक्खियों की 25 प्रतिशत प्रजातियां

एजेंसियां

हाल ही में जर्नल वन अर्थ में छपे एक शोध से पता चला है कि 1990 से 2015 के बीच मधुमक्खियों की करीब एक चौथाई प्रजातियों को फिर से नहीं देखा गया है

हर साल जंगली मधुमक्खियों से जुड़े यह आंकड़ें इंटरनेशनल डेटाबेस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ द्वारा रिकॉर्ड किए जाते हैं, जिनके विश्लेषण के बाद यह निष्कर्ष सामने आए हैं।अनुमान है कि 1990 में जंगली मधुमक्खियों की जितनी प्रजातियां सामने आई थी वो 2006 से 2015 के बीच एकत्र किये आंकड़ों में तीन चौथाई रह गई हैं। शोधकर्ताओं ने म्यूजियम, विश्वविद्यालयों और वैज्ञानिकों द्वारा मधुमक्खियों के बारे में एकत्र किए आंकड़ों के विश्लेषण के बात यह बात कही है। यह शोध जर्नल वन अर्थ में प्रकाशित हुआ है।

इस शोध में तीन शताब्दियों से एकत्र आंकड़ों और मधुमक्खियों की 20,000 से ज्यादा प्रजातियों का विश्लेषण किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि उष्णकटिबंधीय देशों में कीटों और उनकी गिरावट से जुड़े आंकड़ों का आभाव है। यह कमी मधुमक्खियों की प्रजातियों में आई गिरावट को समझने में एक बड़ी बाधा है। ग्लोबल बायोडायवर्सिटी इनफार्मेशन फैसिलिटी (जीबीआईएफ) ने जो आंकड़ें एकत्र किए हैं वो ज्यादातर उत्तरी अमेरिका और यूरोप से जुड़े हैं। जबकि अफ्रीका और एशिया के विषय में अभी भी डाटा की कमी है।

हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगा कि जो प्रजातियां सामने नहीं आई हैं वो विलुप्त हो चुकी हैं। पर इतना तो जरूर है कि वो इतनी दुर्लभ हो गई है कि सामने नहीं आ रही हैं। इस रिपोर्ट के प्रमुख लेखक और जीव विज्ञानी एडुआर्डो जट्टारा के अनुसार "अभी तक यह मधुमक्खियों के लिए प्रलय तो नहीं है पर हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जंगली मधुमक्खियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। 85 फीसदी खाद्यान्न फसलों के लिए महत्वपूर्ण हैं मधुमक्खियां जंगली मधुमक्खियां पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इनके द्वारा किया परागण हजारों जंगली पौधों के विकास के लिए जरुरी होता है। यह 85 फीसदी खाद्य फसलों की पैदावार के लिए मायने रखती हैं। मधुमक्खी प्रजातियों की विविधता और गिरावट स्थानीय, राष्ट्रीय और महाद्वीपों के आधार पर अलग-अलग है, लेकिन आंकड़ें कुल मिलकर इनकी संख्या कमी की ओर इशारा करते हैं। 1990 के दशक में मधुमक्खियों की जिन प्रजातियों के नमूने एकत्र किये जाते रहे हैं उनकी संख्या में कमी आती जा रही है। इसका मतलब है कि यदि इनकी प्रजातियां विलुप्त नहीं तो दुर्लभ तो जरूर होती जा रही हैं और उनके कम ही पाए जाने की सम्भावना है।

मधुमक्खियों में जो कमी आ रही है वो प्रजातियों के आधार पर अलग-अलग है। यदि हैलिकिड मधुमक्खियों की बात करें जोकि मधुमक्खियों की दूसरी सबसे आम प्रजाति है तो उनमें 90 के दशक से 17 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं मेलिटिडे जोकि एक दुर्लभ प्रजाति की मधुमखी है उसमें करीब 41 फीसदी तक की कमी आई है। इससे पहले किए शोधों में भी कीटों के विलुप्त होने की बात सामने आई थी। अप्रैल 2019 में जर्नल बायोलॉजिकल कंज़र्वेशन में छपे शोध के अनुसार अगले कुछ दशकों में 40 फीसदी से भी ज्यादा कीटों पर विलुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। जिसका सबसे ज्यादा असर तितलियों, मधुमक्खियों और गुबरैला पर पड़ रहा है।

आंकड़ों के मुताबिक हर वर्ष 2.5 फीसदी की दर से कीट विलुप्त हो रहे हैं। इनके विलुप्त होने की यह गति स्तनधारियों, पक्षियों और सरीसृपों की तुलना में आठ गुना तेज है। अनुमान है कि इस गति से अगली एक सदी में यह कीट पूरी तरह विलुप्त हो जाएंगे। जट्टारा के अनुसार मधुमक्खियों के साथ कुछ तो ऐसा हो रहा है जिस पर ध्यान देने की जरुरत है। हम पूरे आंकड़ें सामने आने तक इंतजार नहीं कर सकते। हमारे पास अभी भी समय है इसलिए नीति निर्माताओं को इस बारे में सोचना होगा, लेकिन मधुमक्खियां इस बाबत इंतज़ार नहीं कर सकती।

पर्यावरण और लोगों के लिए बड़ा खतरा हैं पुराने होते बड़े बांध

अगले 29 वर्षों में दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी उन बड़े बांधों के साये में होगी जो या तो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं या पूरी करने वाले हैं। ऐसे में उनपर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह जानकारी हाल ही में यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी द्वारा जारी रिपोर्ट में सामने आई है।

यदि वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ लार्ज डेम्स को देखें तो दुनिया में 58,713 बड़े बांध हैं। हालांकि यह लिस्ट अभी भी पूरी नहीं है। इनमें से सबसे ज्यादा बांध चीन में हैं जहां 23841 बड़े बांध हैं, जोकि विश्व के कुल निर्मित बड़े बांधों का 40 फीसदी है। इसके बाद अमेरिका 9,263 और फिर भारत 4,407 का नंबर आता है। करीब 93 फीसदी बड़े बांध केवल 25 देशों में स्थित हैं, जिनमें भारत भी एक है।

पाम ऑयल पैदा करने की कीमत चुका रहे हैं इंडोनेशिया के आदिवासी

एजेंसियां :इंडोनेशिया के पाम ऑयल को आयात करने में भारत और चीन सबसे आगे हैं। इस तेल को निकालने के लिए जंगल काटकर ताड़ के पेड़ लगाए गए जिससे इंडोनेशिया के पापुआ प्रांत के जंगल और आदिवासी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इंडोनेशिया सरकार ने एक दशक पहले पापुआ प्रांत में ताड़ के पेड़ लगाकर इस प्रांत को खेती आधारित व्यापारिक केंद्र में बदलने की कोशिश की थी। आज इंडोनेशिया पाम ऑयल उत्पादन के मामले में विश्व में शीर्ष पर पहुंच गया है। अब तस्वीरों में इस प्रांत के आदिवासियों पर ताड़ की खेती का प्रकृति और लोगों पर असर दिखता है।

तस्वीरों को कोरियन सेंटर फॉर इंवेस्टिगेटिव जर्नलिज्म- न्यूजटापा, 101 इस्ट, अलजजीरा का एशिया-पेसिफिक करेंट अफैयर्स प्रोग्राम के तहत गेको प्रजेक्ट और मोंगाबे में एकसाथ प्रकाशित किया गया है। इंडोनेशिया के पापुआ का बोवेन दिगोल क्षेत्र। घने जंगलों के लिए मशहूर इस इलाके की नई पहचान पाम ऑयल से है। ताड़ के बीजों से निकाले गए तेल को पाम ऑयल कहते हैं। आजकल भारत में इसकी खपत बहुत अधिक है।

कुछ सालों पहले जब यहां प्राकृतिक जंगल थे तो कई महिलाएं यहां साबूदाना जुटाने आया करती थीं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सब बदल गया। पिछले चार वर्षों में यहां के जंगलों में बड़ा बदलाव हुआ है, जिससे पस्कलिना जैसी आदिवासी महिलाएं बेखबर थी। उनके जंगलों को ताड़ की खेती के लिए बेच दिया गया। देखते-देखते यह क्षेत्र ताड़ के जंगल में तब्दील हो गया। ताड़ के पेड़ों से पाम ऑयल निकाला जाता है। यही तेल इंडोनेशिया, भारत और चीन जैसे देशों को निर्यात करता है।

अयु समुदाय के लोग एक वक्त इस जंगल पर राज करते थे, लेकिन वे अपनी ही जमीन पर मजदूर बनकर रह गए हैं। इन जंगलों ने वर्षों से उनका पेट पाला है। अब उन्हें ताड़ उगाने वाली कंपनी से कई बार खाने के लिए कर्ज लेना पड़ता है, जिसे कंपनी वाले बाद में मजदूरी से काट लेते हैं। इस वजह से कई बार उन्हें महीनों काम करने के बाद भी कोई मजदूरी नहीं मिलती और खाने के लाले हो जाते हैं। यहां कुपोषण की समस्या अब आम बात हो गयी। इन सब समस्याओं की शुरुआत जंगल खत्म होने से हुई। यहां के आदिवासियों का पेट पालने के लिए जंगल में भरपूर खाद्य सामग्री मिल जाती थी। लेकिन, अब कंपनी वाले शहरों में खाए जाने वाली चीजें यहां भी उपलब्ध कराने लगे हैं। इसके बारे में इन आदिवासियों में आम राय है कि इसमें जंगल के खाने जितना पोषण नहीं है। वे यह भी नहीं जानते कि शहर से आया खाना किस चीज से बना है।अब ये पाम की खेती की सजा भुगत रहे हैं।

मोबाइल टावर मानव जीवन के लिए खतरनाक

करमनाथ महतो

हमें जीवन में अनेकों सुविधाओं को देने वाला मोबाइल और मोबाइल फोन के टावर हमे सुविधाओ के साथ-साथ अनेको बीमारियां भी दे रहे हैं। ये साइलेंट किलर की तरह हमारे शरीर को अन्दर से खोखला कर रहे हैं,जिससे अधिकतर लोग अनजान हैं और जो जानते है फिर भी बच नही पा रहे। क्योंकि हमारे जीवन शैली मे मोबाइल गहरी पैठ बना चुका है। आज हम बच्चों को मोबाइल जाने अनजाने में खेलने और पढने के लिए दे देते है। बच्चे मोबाइल मे गेम खेलने के साथ-साथ आनलाइन पढाई भी कर रहे हैं। बच्चो को घर बैठे पढने की सुविधा मिल रही है।

आज हमारे अनेको काम आनलाइन हो रहे हैं। परन्तु इसके परिणाम गंभीर बीमारी के रूप मे मिल रहे हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फ्रिक्वेंसी रेडिएशन जो हमारे मोबाइल और मोबाइल टावर से लगातार निकलते है हमारे लिए अति नुकसानदायक है। कभी कभी ये घातक सिद्ध होते हैं। मानव जीवन के साथ-साथ पशु पक्षियो के लिए भी खतरनाक है। बच्चो के लिए तो यह और ज्यादा घातक है।

रेडिएशन से ये प्रमुख बीमारियां हो सकती हैं

- नींद न आना
- बेचैनी
- थकान
- चिड़चिड़ापन
- हृदय संबंधी रोग
- बांझपन
- नपुंसकता
- सरदर्द
- बहरापन
- किडनी फेल होने का खतरा
- हाई ब्लडप्रेशर
- कैंसर

रेडिएशन से बचने के कुछ प्रमुख उपाय

- मोबाइल का कम से कम उपयोग
- मोबाइल को अपने शरीर से दूर रखें
- हेडफोन का उपयोग करें।
- अपने घर के नजदीक टावर न लगायें न लगाने दें।
- स्पीकर आन कर बात करे मोबाइल को कान से न लगाए।
- सोते समय मोबाइल दूर रखें

गुजरात में पाए जाते हैं तैरने वाले ऊंट, तेजी से हो रहें हैं लुप्त

ऊंटों की सामान्य पहचान रेत, रेगिस्तान वगैरह से जोड़कर बनी है। पर गुजरात के कच्छ में खराई ऊंट की प्रजाति पाई जाती है जो तैरने में माहिर होती हैं। यह ऊंट की अकेली प्रजाति है जिन्हें तैरना आता है। ये ऊंट मैंग्रोव और दूसरी समुद्री खर-पतवार खाकर जीवित रहते हैं। मैंग्रोव से तात्पर्य उन पेड़-पौधों से हैं जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। मानसून में ये ऊंट समूहों में तैरकर मैंग्रोव वाले टापुओं पर चले जाते हैं और पूरी बारिश वहीं रहते हैं। बढ़ते उद्योगों की वजह से मैंग्रोव खत्म हो रहे हैं जिससे इन ऊंटों को खाने की समस्या आने लगी है। पूरे गुजरात में मात्र 4500 खराई ऊंट बचे हैं। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऊंचे गर्दन वाला यह जीव रेत के बीच भी तेजी से भागता है। गर्म दिनों में कई दिनों तक बिना पानी के रह सकता है। हालांकि, कम ही लोग होंगे जो यह जानते होंगे कि ऊंटों की एक ऐसी प्रजाति भी है जो रेत के साथ-साथ उफनते समंदर में भी इतनी आसानी से यात्रा कर सकती है। खराई प्रजाति के ये ऊंट गुजरात में पाए जाते हैं। खराई यानी खारे पानी का ऊंट। तैरने वाले इन ऊंटों को गुजरात के कच्छ क्षेत्र में आसानी से देखा जा सकता है। इनका खाना समुद्र के आसपास उगने वाले खर-पतवार और मैंग्रोव हैं। मैंग्रोव से तात्पर्य उन पेड़-पौधों से हैं जो तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं और खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। अब बदलते वक्त में तथाकथित 'विकास' की मार अब इनके जीवन को भी प्रभावित करने लगी है। अब मैंग्रोव के जंगल खत्म हो रहे हैं और आए दिन भूख की वजह से ऊंटों की मृत्यु हो रही है। इस खास प्रजाति के ऊंटों की संख्या तेजी से कम हो रही है। इस तरह पानी में तैर सकने वाले अनोखे खराई ऊंट विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए हैं।

ऊंट की उत्पत्ति के पीछे एक अनोखो मिथक भी जुड़ा हुआ है। कच्छ की किंदवंतियों में कहते हैं कि 400 वर्ष पहले रैबारी परिवार के दो भाई एक ऊंट के मालिकाना हक को लेकर झगड़ पड़े। मामले को सुलझाने के लिए वे सांवला पीर के दर पर गए। पीर ने मोम का एक विशाल ऊंट बनाया जो कि असली ऊंट जैसा दिख रहा था। पीर ने दोनों भाइयों को अपना-अपना ऊंट चुनने को कहा। बड़ा भाई ने असली ऊंट पहचान लिया और छोटे के हिस्से में मोम का नकली ऊंट आया। सांवला पीर ने छोटे भाई को मोम के ऊंट को समुद्र में विसर्जित करने की सलाह दी। ऐसा करने के बाद हजारों ऊंट समुद्र में से निकलकर छोटे भाई के पीछे हो चले। ये सब खराई ऊंट थे। रैबारी और जाट, दो समुदाय के लोग इस ऊंट को परंपरागत रूप से पालते आ रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि राजाओं ने इन दोनों समुदाय को ऊंट पालने की जिम्मेदारी दी थी। मरुस्थल के जहाज के तौर पर पहचाने जाने वाले ऊंटों की एक प्रजाति ऐसी भी है जो पानी में तैर सकती सकती है। खराई ऊंटों का एक जत्था। तस्वीर- सहजीवन मरुस्थल के जहाज के तौर पर पहचाने जाने वाले ऊंटों की एक प्रजाति ऐसी भी है जो पानी में तैर सकती सकती है। खराई ऊंटों का एक जत्था। तस्वीर- सहजीवन इस ऊंट से जुड़ा इतिहास कुछ धुंधला सा हो सकता है लेकिन इतना जरूर है कि इस प्रजाति के ऊंटों को काफी सम्मान से देखा जाता है। कुछ वर्ष पहले तक इन्हें इतना पवित्र माना जाता था कि इससे निकला दूध और ऊन का क्रय-विक्रय नहीं होता था। नर ऊंटों का उपयोग छोटी गाड़ी खींचने के लिए किया जाता है, जिससे व्यापारी अपना सामान अंदरुनी गांवों में ले जाते हैं। महज ढुलाई के लिए ऊंट का उपयोग होने की वजह से पालकों की आर्थिक स्थिति कुछ ठीक नहीं है। इस ऊंट के अस्तित्व पर सबसे बड़ा संकट मैंग्रोव के टापुओं से इनका छिनता अधिकार है। मैंग्रोव पर भी विकास का संकट मंडरा रहा है और इन ऊंटों के लिए उपलब्ध भोजन में कमी आ रही है। ऊंट बारिश के मौसम में मैंग्रोव के टापू तट से दूर हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में हर वर्ष इस मौसम में ऊंट, तैरकर टापू पर जाते हैं और वहीं रहते हैं। इन ऊंटों के साथ इनके पालक भी वही रहते हैं और ऊंटनी के दूध पीकर अपना पेट भरते हैं। मैंग्रोव के जंगल पर ऊंट साल में आठ महीने निर्भर रहते हैं। खाने को समुद्र के किनारे हरे पत्ते और पीने को बारिश का जमा हुआ पानी मिल जाता है। गर्मियों में ये ऊंट अपने पालक के साथ गावों की तरफ लौटते हैं जहां उनके खाने-पीने की व्यवस्था की जाती है।

बदलेगी 2021 में पर्यावरण संरक्षण की दशा और दिशा ?

मनोरंजन सिंह

बात प्रकृति की हो ऐसा लगता है साल 2021 एक निर्णायक वर्ष साबित होगा। निर्णायक इसलिए क्योंकि इस साल दुनिया भर की सरकारें और पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय संस्थाएं प्रकृति को हो रहे नुकसान को रोकने और बुरे असर को पलटने के लिए एकजुट हो रही हैं।

इस क्रम में बीते 11 जनवरी को फ्रांस में वन प्लैनेट समिट का आयोजन हुआ। इस समिट का उद्देश्य था जैव विविधता के नुकसान के मुद्दे को राजनीतिक प्राथमिकता बनाना और इस नुकसान की भरपाई के लिए ठोस समाधानों का प्रस्ताव करना। दरअसल वन प्लैनेट समिट में हाई अम्बिशन कोअलिशन फॉर नेचर एंड पीपल नाम के 50 देशों के एक गुट ने पृथ्वी की सतह के एक तिहाई हिस्से को संरक्षित करने की प्रतिज्ञा है। लेकिन विशेषज्ञ कह रहे हैं कि 30 प्रतिशत नहीं, जरूरत 50 फीसद के संरक्षण की है। पचास देशों के इस गुट में यूके और छह महाद्वीपों के देश शामिल हैं।

फ्रांस में आयोजित वन प्लैनेट समिट में हालाँकि चर्चा का मुख्य बिंदु जैव विविधता था लेकिन इन मुद्दों की तरलता के चलते समिट में बातें जैव विविधता, मरुस्थलीकरण और जलवायु मुद्दों पर केन्द्रित हो गयीं क्योंकि यह मुद्दे परस्पर जुड़े हुए हैं। अपनी प्रतिक्रिया देते हुए आवाज नामक संस्था के कैम्पेन डायरेक्टर, ओस्कर सोरिया, कहते हैं, ''दुनिया के नेता अब यह महसूस कर रहे हैं कि जैव विविधता का नुकसान न केवल हमारी खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा है, बल्कि यह हमें महामारी की चपेट में ले रहा है और हमारी जलवायु को स्थिर करने के लिए किसी भी प्रगति को कमजोर करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि हमें 2030 तक जैव विविधता के नुकसान को दूर करने के लिए तीस प्रतिशत नहीं, कम से कम आधे ग्रह की रक्षा करने की आवश्यकता है। और ऐसा तब ही सम्भव है जब स्थानीय लोगों का साथ हो, उनसे परामर्श किया जाये, उनके अधिकारों का सम्मान हो, और उनके अनुभवों को सुना जाये।''

वहीं वन अर्थ संस्था के मैनिजिंग डायरेक्टर, कार्ल बुर्कार्ट कहते हैं, "हमें दुनिया के शेष प्राकृतिक आवास को संरक्षित और बहाल करना चाहिए, जो पृथ्वी का 50% हिस्सा है। इसके अलावा, दुनिया को तेजी से स्वच्छ, नवीकरणीय ऊर्जा और पुनर्योजी कृषि प्रणालियों की ओर बढ़ना चाहिए। और इन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए हमें मूलनिवासियों के भूमि अधिकारों को बनाए रखना होगा। इसके साथ, समिट में नेचर रिलेटेड फाइनेंसियल डिसक्लोज़र नाम की एक टास्क फ़ोर्स भी लांच की गयी। इस टास्क फ़ोर्स से कंपनियों को जलवायु और जैव विविधता लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद मिलेगी। लक्ष्य जैव विविधता पदचिह्न को मापने के लिए वैश्विक उपकरण स्थापित करना है। एक अनौपचारिक कामकाजी समूह, जिसे विश्व बैंक समर्थन करता है, कार्यबल के कार्यस्थल और शासन को परिभाषित करने के लिए प्रारंभिक कार्य कर रहा है। इस कार्यबल के लिए सफलता का दूसरा तत्व प्रकृति जोखिम और प्रभाव के उपयुक्त मीट्रिक विकसित करने की क्षमता होगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस समिट को ख़ास बनाती है वो है वन हेल्थ नाम की पहल जिसके अंतर्गत भविष्य की महामारियों से बचने के लिए शोध किये जायेंगे। फ़्रांस और जर्मनी के सहयोग से बना यह कार्यक्रम ख़ासा महत्वपूर्ण है। यह पहल चिकित्सा, पशुचिकित्सा, और संरक्षण समुदायों के बीच पुल और निर्माण पर जोर देती है, जो परंपरागत रूप से एक साथ काम नहीं करते हैं। वहीं अफ्रीका की तरफ से इस समिट में ग्रेट ग्रीन वाल प्रोग्राम का आगाज़ हुआ जिसके अंतर्गत सहारा रेगिस्तान के आसपास मरुस्थालिकरण से निपटने के लिए 14 बिलयन डॉलर की राशि जुटाने का काम होगा।

ऐसी ही तमाम पहल हुईं इस समिट में जो पर्यावरण संरक्षण की वैश्विक कोशिशों की दशा और दिशा बदल सकती हैं।

M. K. ENTERPRISES
Shop No.-5, Laxmi Palace, Court Compound, Ranchi,
Ph. 9334710615
समस्त पशुओं के दवाओं के थोक विक्रेता

गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर सभी झारखंड वासियों को असीम शुभकामनायें

E ZONE CARE

Software Problem, Motherboard Chip-Level Repair, Laptop AC Adapter Repair and Replacement, Laptop LCD Screens Repair and Replacement, Dead Laptop Problems, No Display Problem, LCD Dim Display Problem, LCD White Display Problem, BIOS Password Problem, all type of Laptop repair and service

- **Repair your laptop with 3-month warranty.**

info@ezonecare.in, ezonecare.in
Rospa Tower 3RD Floor, Main Road, Ranchi 93108 96575, 70047 69511
Mon - Fri 10:30 am - 7:00 pm
SUNDAY CLOSED

अखबार के स्वामी सन कम्युनिकेशन के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मनोरंजन सिंह द्वारा मेसर्स डी. बी. कॉर्प लिमिटेड,प्लॉट नं535 एवं 1272 ललगुटवा पुलिस स्टेशन, रातू, रांची (झारखंड) से मुद्रित एवं सन कम्युनिकेशन,अपोजिट कब्रिस्तान गेट नं.-2,रातू रोड, रांची- 834001 (झारखंड) से प्रकाशित। संपादकः एम.के.शर्मा * (पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिये उत्तरदायी)आर.एन.आइ. पंजीयन क्रमांक : **JHAHIN/2019/78094**, email:greenrevolt2019@gmail.com.☎ 0651-2283018, 8539978825, 8825374626. समस्त विवाद रांची न्यायालय के अधीन होंगे।